Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 22 अंक-16 रायपुर, शुक्रवार, 8 फरवरी 2019 पृष्ठ-8 मूल्य- 2 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कोई नया कर का प्रस्ताव नहीं

हाईवे चैनल

रायपुर, 8 फरवरी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पार्टी के जनघोषणा के अनुरूप जनकल्याणकारी बजट तैयार करने का विश्वास दिलाया तथा बजट को छत्तीसगढ़ की जनता में खुशहाली लाने की कार्ययोजनाओं से भरा हुआ बजट बताया। यह नई कांग्रेस सरकार का पहला बजट है और यह पहला बजट प्रदेश के किसानों और कृषि विकास के कार्यों को राहत देने की भरपूर कोशिश के साथ सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा कर दिया गया है वहीं प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा गया है।

उन्होने कहा की छत्तीसगढ़ की 75 फीसदी आबादी गाँव में निवास करती है और आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। कृषि और किसानों के विकास से ही हमारे गाँव समृद्ध होंगे। इसी अवधारणा को लेकर हमारी सरकार का पहला बजट प्रदेश के किसानों और कृषि विकास के कार्यों पर केन्द्रित है। मानसून की अनिश्चितता एवं वर्षा आधारित कृषि ही हमारे प्रदेश में किसानों का भविष्य निर्धारित करती रही है। अधिकांश किसान खेती किसानी का काम अल्पकालीन कृषि ऋणलेकर करते हैं किन्तु समय पर वर्षा का पानी नहीं मिलने से फसलोंका नुकसान तोझेलते ही हैं साथ ही कर्जा चुकाने का बोझ भी उन पर अलग से आता है। 4.कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार की किसानों की आय दुगुनी करने के विषय पर गठित समितिकी रिपोर्ट के वॉल्यूमदो में उल्लेख है कि वर्ष 2015-16 में अखिल भारतीय स्तर पर कृषकपरिवारकी अनुमानित औसत वार्षिक आय 96 हजार 703 रू.की तुलना में छत्तीसगढ़ के कृषक परिवार की आय मात्र 64 हजार थी। समिति का यह भी आकलन है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल से होने वाली आय में 2004-05 से 2008-09 की तुलना में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में कमी आयी है। विचाराधीन अवधि में धान की पैदावार में बढ़ोत्तरी एवं उपार्जन मूल्य में वृद्धि के बावजूद किसान की आय में कमी का मुख्य कारण लागत मूल्यमें वृद्धि होना है। 5.कृषि लागत मूल्य में कमी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहला कदम उठाया है, किसानों को पुराने कर्जों के कुचक्रसे मुक्ति दिलाने का। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के 6 हजार 230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय पिछले 17 दिसम्बर को लिया थाऔर अब हमने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिये गये लगभग34 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋणोंको भी माफ करने का निर्णय लिया है। कृषि ऋण की माफी के लिए तीसरे अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने 4 हजार 224करोड़ की राशि का प्रावधान किया थाऔर शेषराशि के लिए भी समुचित प्रावधान किया है। .छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है और राज्य को तो धान का कटोरा ही कहते थे। किन्तु पूर्व सरकार की नीतियों से धान की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गई। किसानों को धान का लागत मूल्य निकालना मुश्किल हो गया और दिनों-दिन उनकी आर्थिक स्थितिकमजोर होने लगी। इसीलिए हमने हमारे जन घोषणा पत्र में 2500 रू.प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का वादा किया था। हमने अपने वादे को पूरा भी किया और खरीफ 2018 के धान को हमने किसानों से 2500 रू.की दर पर खरीदा। आने वाले वर्षों में भी हम अपने वादे पर कायम हैं और 2019-20 के बजट में भी 2500 रू.प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान करने के साथ-साथ गैर-जरूरी एवं प्रत्यक्ष लाभ न देने वाली योजनाओं के प्रावधानोंमें संशोधन पर भी विचार किया गया है। योजनाओं का समुचित परीक्षण करकेहमनेप्राथमिकता वाली योजनाओं केलिए अधिक वित्तीय संसाधन जुटाये है। साथ ही बजट घाटे को नियंत्रित रखने का भी युक्तियुक्त प्रयास किया है।

आर्थिक स्थिति

वर्ष 2018-19 केआर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2018-19 मे राज्य के सकल घेरलू उत्पाद में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जो इसी अवधि के लिए अनुमानित अखिल भारतीय सकल घेरलू उत्पादवृद्धि दर 7.2 प्रतिशत की तुलना में कम है। 8.2.वर्ष 2018-19 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 3.8 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध राज्य में 3.9 प्रतिशतकी वृद्धिअनुमानित है राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में 7.8प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत वृद्धि,और सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 7.3प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध राज्य मेंसेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशतअनुमानित है इस प्रकार राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तरसे कम रहना अनुमानित है। 8.3.राज्य का सकल घेरलू उत्पाद प्रचलित दर पर वर्ष 2017-18 में2 लाख 84 हजार करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3 लाख12 हजार करोड़ होना अनुमानित है, जो की पिछले वर्ष की तुलना में 9.66 प्रतिशत अधिकहै। वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घेरलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.21 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 47.17 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 35.63 प्रतिशत अनुमानित हैं।

नई सरकार का पहला बजट

58.5.वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 25 हजार 397 रू.अनुमानित है जबकि इसी अवधि मेंराज्य मेंप्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 रू.का अनुमान है राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि राज्य स्तर पर वृद्धि 7.9 प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार राज्य में प्रति व्यक्तिआय वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर की तुलना में केवल दो-तिहाई के लगभग है। 9.अध्यक्ष महोदय,राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर की तुलना में राज्य की आर्थिक विकासदर कम है जिसमें बढ़ोत्तरी करने केलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें राज्य के आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली के लिए उपलब्ध संसाधनों काअधिकसंवेदनशीलता के साथ बेहतर उपयोग और कड़ी मेहनत करने की जरूरत हैं। इस लोक कल्याणकारी बजट के माध्यम से हमारी सरकार कृषि क्षेत्रके साथ-साथ संपूर्णअर्थव्यवस्था को मजबूतकरने का काम करने का प्रयास कर रही हैं।10.अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमनेउन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनसे किसानों एवं अल्प आय वाले परिवारों कोयोजनाओं में प्रावधानित राशि का सीधा लाभ मिले। योजनाओं का पैसासीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचे।चाहे वो पैसा ऋण माफी का हो या धान प्रोत्साहन का। पैसा किसान के हाथ में मिले ताकि वो अपनी इच्छा से अपने अधूरे सपने पूरा कर सके। अपनी मर्जीसे अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ सके। इस बजट में ऐसी योजनाओं के लिए राशि रखी गई है, जिनसे महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिले तथा युवाओं और बच्चोंको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

.किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में 2500रू.प्रति क्विंटल की दर सेधान खरीदी हेतु 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के साथ-साथ हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों द्वारा बांटे गये अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफकरने का फैसला लिया है। बजट में किसानों का कृषि ऋण माफकरनेके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। .गरीब परिवारों को भरपेट भोजन की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल देने का निर्णय लियाहै। इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 4 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। घेरलू उपभोक्ताओं काबिजली बिल हाफकरने की दृष्टि से विद्युत देयकों में 400 यूनिटतक विद्युत व्यय-भार पर आधी छूट का लाभ सभी घेरलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट का लाभ 1 मार्च 2019 से दिया जायेगा और उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में मिलने वालेबिजली बिल पर आधी छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 400 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

बजट में कुछ खास बातें

- बेमेतरा में नया कृषि विश्वविद्यालय
- गरियाबंद में 100 बिस्तर का अस्पताल
- बालोद में महिला महाविद्यालय
- विधायक निधि 1 से 2 करोड़
- मध्यान्ह भोजन मानदेय 12 से 15 सौ रुपए
- मनरेगा पर 1542 करोड़ का प्रावधान
- हर गांव में 3 एकड़ में गौठान
- दिव्यांगों की विवाह राशि 50 से 1 लाख
- गांव के तालाबों को सोलर पंप से भरा जाएगा

711.5.जनप्रतिनिधियों को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अधिक जवाबदेही के साथ काम करने का अवसर देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 182 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। .पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को रिस्पान्स भत्ता देने के लिए 45 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है। .प्रदेश में उत्पादित खाद्य-पदार्थ,फल-फूल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर किसानों के लिए अधिक आय एवं रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रथमत: 5 नये फूड पार्क प्रारंभ करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आश्रम एवं छात्रावासों में रहने वाले प्री-मैट्रिकस्तर के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग केविद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की राशि 900 रू.प्रति माह से बढ़ाकर 1000रू.प्रति माह,तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता की राशि 500 रू.प्रति माह से बढ़ाकर 700 रू.प्रति माह की गई है। इसके लिए 27 करोड़57 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 11.9.स्कूलों में संचालित मध्याह्नभोजन कार्यक्रम में खाना बनाने वाली रसोईयों को 1200 से बढ़ाकर 1500 रू.प्रति माह मानदेय दियाजायेगा। इसके लिए बजट में 26करोड़59 लाखका अतिरिक्त प्रावधान है।

वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ एवं दामाखेड़ा के समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण खेती और किसानी के काम को राज्य में लाभकारी आजीविका के रूप में विकसित कर किसानों की खुशहाली लौटाना हमारी 2य2सरकार का पहला संकल्प है। इसके लिएकाम के साथ-साथहमनेविभाग के नाम को भी सही पहचान देने का प्रयास किया है। इसलिए कृषि एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकरकृषि विकास,किसान कल्याणऔर जैव प्रौद्योगिकीविभाग करने का हमने निर्णय लिया है। किसानोंके कल्याण की योजनाओं के लिएइस वर्ष 21 हजार 597करोड़ काकृषि बजट तैयारकिया गया है जो गत वर्ष के कृषि बजट के डेढ़ गुनासे भी अधिक है। 13.कर्जों के कुचक्र से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु ग्रामीण बैंक एवं सहकारीबैंकोंसे बांटे गये ऋणके साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों द्वारा बांटे गयेलगभग 4 हजार करोड़ के अल्पकालीनकृषि ऋणको भी माफकरने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब तक लगभग 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋणकी माफी सेप्रदेश के लगभग 20लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 4 लाख ऐसे ऋणी किसान भी लाभांवित होंगे जो बकाया धन चुकता न कर पाने के कारण बैंकों से ऋण नहीं ले पा रहे थेऔर निजी साहूकार एवं सूदखोरों से कर्ज लेने के लिए विवश थे। ऐसे किसान अब राज्य शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना में पुन: ग्रामीण अथवा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि ऋण की माफी के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।14.कृषि ऋणकी माफी केसाथ-साथ किसानों को राहत देने के लिए 207 करोड़ का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है जिससे 15 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 15.खरीफ2019 के लिए राज्य में 85 लाख टन धान खरीदी का अनुमानहै। कृषकों से धान की खरीदी 2500 रू.प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। इसके लिए 5 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान है। प्रदेश के 17 लाख से भी अधिक किसानों को इस2का सीधा लाभ मिलेगा।

महागठबंधन है महामिलावटी

राज्य की सरकार को बताया कठपुतली

हाईवे चैनल

रायपुर, 8 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां रायगढ़ के कोडारतराई एयरस्ट्रिप में एक आमसभा को संबोधित किया। मोदी सुबह 10.05 बजे विमान से मानाविमान तल पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए प्रशासन की ओर से नगरीय निकाय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सीके खेतान आदि मौजूद थे। स्वागत के बाद नरेन्द्र मोदी हेलीकाप्टर से रायगढ़ के लिए रवाना हुए।

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद रायगढ़ की आमसभा में कांग्रेस पर बरसे मोदी

रायगढ़ में जमकर बरसे मोदी कांग्रेस की नीतियों को बताया भ्रष्टाचारी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असली राजनीति भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टचारियों का साथ दो, मैंने उनमें से नहीं जो किताब खोलने से डरते है। किसी प्रश्न पर अहसान नहीं करता मैं बल्कि जवाब देता हूं। यहां की सरकार छत्तीसगढ़ के गरीबों का हक छीन रही है। दिल्ली से उनको यही संस्कार मिलती है। मोदी ने विपक्षियों के महागठबंधन को महामिलावटी करार दिया तथा जनता को उससे बचने की सलाह दी। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर दिल्ली में बक्सा भेजने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को प्रदेश में नहीं आने देना चाहती। उन्होंने राज्य सरकार पर यहां के गरीब लोगों को मोदी केयर से महरूम रखने का भी आरोप लगाया। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मयानगुरी में भी रैली को संबोधित करेंगे। पिछले साल विधानसभा चुनावों में हार के बाद छत्तीसगढ़ में यह प्रधानमंत्री की पहली रैली है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा- पीएम मोदी की रैली को लोकर रायगढ़ के कोदातराई में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस रैली का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में लोकसभा चुनावों से पहले उत्साह भरना है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी फलकाटा-सलसालाबारी सेक्शन के चार लाईन के नेशनल हाईवे-31डी की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यलय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 41.7 किलोमीटर लंबा यह नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बनेगा और इसमे कुल 1938 करोड़ की लागत आएगी। रायगढ़ की सभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी मौजूद थे।

डीजी मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज

हाईवे चैनल

रायपुर, 8 फरवरी 2019। इओडब्लू ने अब तक कि सबसे बड़ी करवाई करते हुए अपने ही पूर्व छ्रत्र मुकेश गुप्ता और स्क्र नारायणपुर रजनेश सिंह के खिलाफ में देर रात अपराध दर्ज कर लिया। दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वे बेहद गंभीर और गैर जमानती है। डीजी और जिले के एसपी जैसे अफसरों के खिलाफ अपराध कायम करने का प्रदेश का यह पहला मामला होगा। मौजुदा समय में प्रदेश में डीजी पद पर पदस्थ मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह पर आरोप है कि इन दोनो ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए अपराधिक षड्यंत्र किया, कूटरचित दस्तावेज तैयार किए,अवैध रुप से फोन टैपिंग कराया गया और न्यायालयीन प्रक्रिया को गुमराह किया।

फोन टैपिंग कर फर्जी मामला गढ़ने का आरोप

दिलचस्प है कि यह उस बहुचर्चित नान मामले की जाँच के दौरान सामने आया जिसके लिए पृथक से SIT गठित हुई है। ईओडब्लू और एसीबी की ओर से दर्ज FIR 6/2019 है जिसमें मुकेश गुप्ता तत्कालीन ,छ्रत्र ऐसीबी और इओडब्लू आरोपी क्रमांक एक जबकि रजनेश सिंह तत्कालीन एसपी एसीबी आरोपी क्रमांक के रुप में दर्ज है। प्रदेश के शायद सबसे बडे घटनाक्रम के रुप में पहचाने जाने वाले इस मामले में डीजी मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ धारा 166,166A (b),167,193,194, 196, 201, 218, 466, 467, 471 और 120 B के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस FIR को केवल इस रुप में देखना कि यह प्रदेश के सबसे दबंग आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ उसी इओडब्लू और एसीबी ने दर्ज की है जहाँ मुकेश गुप्ता पदस्थ थे तो यह आप गलत है। मामला इससे भी आगे जाता है क्योंकि यह जिस प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने,न्यायालय को छल करने, अपराधिक षड्यंत्र करने,साक्ष्य गायब करने और अवैध फोन टैपिंग करने के गंभीरता आरोप लगे हैं वह मामला नान का है। यह बहुत हद तक संभव है कि अदालत में चल रही नान प्रकरण को लेकर विधिक कार्यवाही पर इस स्नड्ढक्र का बेहद गंभीर असर पड़े।

कुमारस्वामी ने ऑडियो क्लिप जारी कर विधायकों को लुभाने का लगाया आरोप, येदियुरप्पा ने खारिज किया

बेंगलुरु, 8 फरवरी (एजेंसी)। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को उन्होंने दो ऑडियो क्लिप जारी किए जिनमें भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, जद(एस) विधायक नागन गौड़ा को कथित रूप से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा उनकी सरकार गिराना चाहती है और यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जानकारी में हो रहा है. हालांकि, येदियुरप्पा ने ऑडियो क्लिप को ''फर्जी बताते हुए दावों को खारिज किया है. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश होने से पहले एक प्रेस वार्ता में कुमारस्वामी ने दोनों ऑडियो क्लिप जारी किए. उन्होंने दावा किया कि दोनों क्लिप में येदियुरप्पा, जद(एस) विधायक नागन गौड़ा को कथित रूप से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं.

राफेल मामला गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा : सीतारमण

नई दिल्ली, 8 फरवरी (एजेंसी)। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी सदस्यों ने राफेल विमान सौदे (ऋड्डद्घड्डद्यद्ग ष्ठद्गड्डद्य) को लेकर राज्यसभा में शुक्रवार को भारी शोर-शराबा किया जिससे कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई। इसके अलावा लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने राफेल को लेकर हंगामा किया। राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इसी बीच कांग्रेस के सदस्य एक अंग्रेजी अखबार की खबर की कतरन हाथ में लेकर आसन के समीप आ गये। राफेल मुद्दे से जुड़ी खबर की कतरन दिखाते हुए विपक्षी सदस्य %चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के साथ ही वामपंथी दल, तेलुगूदेशम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी आसन के समीप आ गये और राफेल मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। निर्मला सीतारमण ने राफेल मुद्दे पर लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से विषयों के बारे में समय-समय पर जानकारी लेना हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट से मायावती को झटका, मूर्तियों पर खर्च जनता का पैसा लौटाना होगा

नई दिल्ली, 8 फरवरी (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके संभावित विचार में लखनऊ और नोएडा में अपनी तथा बसपा के चुनाव चिह्न हाथी की मूर्तियां बनवाने पर खर्च किया गया सारा सरकारी धन मायावती को लौटाना होगा। कोर्ट एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक धन का प्रयोग अपनी मूर्तियां बनवाने और राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, हमारे संभावित विचार में मायावती को अपनी और चुनाव चिह्न की मूर्तियां बनवाने पर खर्च हुआ सार्वजनिक धन सरकारी खजाने में वापस जमा करना होगा।

पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह अभी संभावित विचार है क्योंकि मामले की सुनवाई में कुछ वक्त लगेगा। पीठ ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई दो अप्रैल को होगी। बता दें कि हाथरस निवासी गौरव अग्रवाल की आरटीआई के जवाब में कई साल पहले उप्र निर्माण निगम ने बताया था कि मायावती की लखनऊ में लगी मूर्तियों पर 3.50 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कुछ मूर्तियां डीपीएम डिजायन अहमदाबाद ने बनाईं। इन पर 322 लाख रुपये खर्च हुए। रामसुतार फाइन आर्ट वर्क्स, नोएडा द्वारा तैयार मूर्ति पर 13.62 लाख रुपये खर्च हुए।